Rural Sanitation Schemes in West Godavari District

7096. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposal has been submitted by Government of Andhra Pradesh to implement various rural sanitation schemes in West Godavari District in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether approvals have been given for rural sanitation schemes in West Godavari District in 1994-95?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

J.R.Y. in AJP.

7097. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there has been any emphasis to monitor the local employment content generated by the J.R.Y.;

(b) whether it is a fact that the extent of local employment generation has been insignificant in most areas implementing schemes under J.RY.;

(c) the measures being taken to increase the content of involvement of local labour in J.R.Y. schemes;

(d) whether it is a fact that some panchayats are not conscious of this objective in Andhra Pradesh while implementing J.R.Y. programme; and

(e) the measures proposed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI REMESH-WAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) to (e) Primary objective of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) has been to generate additional gainful employment for the unemployed and under-employed local persons in the rural areas. The implementing agencies, namely, Zilla Parishads/District Rural Development Agencies (DRDAs) and Village Pancha yats have to get works executed only through local labour, as contractors are not psrmitted to be engaged for execu tion of any of the works under JRY.

To ensure the strict implementation[1] of this criteria, a series of measures have been taken to monitor the implementation of JRY throughout the country. These State Governments are required to draw a schedule of inspection for each supervisory level officer at the State/District/Block levels to review the qualitative aspects of the programme. In addition, the State Level Coordination Commi'tees (SLCCs) for Rural Development Programme also monitor the implementation of JRY.

The Ministry of Rural Development has recently introduced a system of area officers with a view to effectively monitoring the implementation of various programmes of Rural Deve lopment including JRY. Under this scheme. Senior Officers of the rank of Deputy Secretary and above have been allocated one or two States each. They are required to visit the States allocated to them and gave a feed back on the implementation of Rural Development Programmes including the employment of local labour under JRY.

बस्तर में सड़कों, पुलों श्रौर पुलियों का निर्माण

7098. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में सड़कों, पुलों श्रौर पुलियों के निर्माण की कोई परियोजना भारत सरकार को उसकी मंजूरी श्रौर श्रावंटन

के लिए भेजी थी यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई आवंटन किया है और यदि हां, तो यह आवंटन राशि कितनी है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो यह वित्तीय सहायता कब तक प्रदान की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल):(क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से बस्तर जिले में सड़कों, पुलों और पुलियों के निर्माण की कोई परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय को उस की मंजूरी और आवंटन के लिए प्राप्त नहीं हुई है । ग्रामीण सड़कें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है और इसके लिए राज्य योजना /बजट में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति

7099. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुचारू व्यवस्था करने, नलकूपों तथा हैंडपम्पों को बदलने और उनकी मरम्मत के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कुल व्यय का कितना प्रतिशत वहन किया जाता है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त कार्यों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में केन्द्र से कोई सहायता राशि की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष वार राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या केन्द्र ने मध्य प्रदेश सरकार को मांगी गई राशि उपलब्ध करा दी है; यदि हां, तो कब और कितनी राशि प्रदान की गई; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत उप मिशनों और मिनी मिशन के अंतर्गत गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराने तथा जल सप्लाई योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले कुल खर्च का प्रतिशत नीचे दिया गया है :--

(क) **त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम**

सामान्य	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मैचिंग प्रावधान के आधार पर 100 प्रतिशत ।
मरूभूमि वाले विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्र	मैचिंग प्रावधान की शर्त के बिना 100 प्रतिशत ।

(ख) उप मिशन —75 प्रतिशत